के आदेश में निर्देश दिया था कि आवेदकों को वरीयता पुनः निर्धारित की जाए। आवेदकों में श्री एच. आर. यादव भी शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने 28 मार्च, 1989 के निर्णय के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का अनुमोदन कर दिया था। उक्त आदेश को कार्यान्वित कर दिया गया है।

रोजगार में कथित वृद्धि

2205. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मई, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" समाचार में "रोजगार में 4.3 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि, पी एच डी सी सी आई" शीर्षक से प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है, जिसमें गरीबी उन्मूलन के उपाए बताए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उक्त सुझाव के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेय गोवर्धन) : (क) से (ग) यह समाचार, "रोजगार सृजन के लिए कार्यनीति: कुछ मुद्दे" नामक अध्ययन के संदर्भ में है, जो अप्रैल, 1990 में पी एच डी सी सी आई द्वारा किया गया। अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि यदि आठवीं योजना के दौरान सभी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाना है तो रोजगार सृजन को 4.3 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ाना होगा, इसमें यह भी बताया गया है कि आठवीं योजना अवधि में बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन किया जा सकता है यह बात सोचना विवेकपूर्ण नहीं होगा, लेकिन यह कि इस उद्देश्य के लिए दीर्घावधिक कार्यनीति तैयार करना वांछनीय होगा। इस अध्ययन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव हैं-जनसंख्या संवृद्धि, निरक्षता और खराब स्वास्थ्य में कमी करने; व्यावसायिक प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने, आवश्यकताओं के अनुरूप जनशक्ति आयोजना और जनशक्ति विकास, आयोजना के विकेन्द्रीकरण, स्वरोजगार पर अभिकेन्द्रण, स्थानीय, संसाधनों के अधिकतम उपयोग, भूमि विकास, कृषि और उद्योगों तथा ग्रामीण व शहरी केन्द्रों के बीच बेहतर सम्पर्कों का विकास; प्रशिक्षण, वित्त व्यवस्था, आधार संरचना तक अभिगम इत्यादि के प्रावधान के माध्यम से असंगठित क्षेत्र का संवर्द्धन और संगठित क्षेत्र विशेष कर निजी, संगठित क्षेत्र की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उपाय जैसे निवेश की स्थिति सुधारने के लिए मांग, पूर्ति, आधार संरचना इत्यादि बाधाओं का निराकरण निवेश की स्थिति सुधारने के लिए, औद्योगिक रुग्णता से निपटना, औद्योगिक संबंधों के परिदृश्य का सुधार, सहायक उद्योगीकरण, निजी निर्माण क्रियाकलापों और तृतीयक क्षेत्र का संवर्द्धन करने के कदम उठाए जाने चाहिए।

आठवीं पंचवर्षीय योजनायें तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कार्य योजना का कार्यान्वयन

2206. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस कलेंडर वर्ष के शुरू में देश के ग्रामीण तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक कार्य योजना के कार्यान्वियन की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या कथित कार्य योजना के कार्यान्वियन का काम शुरू हो गया है; और